

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर  
जिला-रायपुर

क्रमांक 114/एफ 2019-55-00016/वि/नि/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11/2/2021  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़

विषय:-सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में न मांग प्रमाण-पत्र तथा न जांच प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक बी-25/26/97/पी.डब्ल्यू.सी/चार, दि.12.12.1997

—0—

राज्य शासन द्वारा उपरोक्त विषय में समय-समय पर कई निर्देश प्रसारित किये गये हैं, जिनका उद्देश्य था कि इन निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कर सेवानिवृत्त सेवकों को शीघ्रता से न मांग प्रमाण पत्र तथा न जांच प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके और उन्हें पेंशन परिलाभों में विलम्ब न हो, परन्तु ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम "आभार आपकी सेवाओं का" के रिपोर्ट से राज्य शासन के ध्यान में आया है कि बहुत से प्रकरणों में न मांग प्रमाण पत्र तथा न जांच प्रमाण पत्र नियुक्तकर्ता अधिकारी के स्तर से समय से जारी नहीं किये जाने के कारण लंबित रहते हैं। इसके कारण पेंशन प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब की स्थिति निर्मित हो जाती है।

2/ ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम "आभार आपकी सेवाओं का" संबंधी वित्त निर्देश 28/2018 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिलिपि संलग्न) की कंडिका (4) की तालिका के सरल क्रमांक 2 एवं 3 में न मांग प्रमाण-पत्र एवं न जांच प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की निम्नानुसार समय-सीमायें निर्धारित की गई है:-

कंडिका (4) की तालिका का सरल क्रमांक	माड्यूल का नाम एवं मुख्य कार्य	कार्य का विवरण	समय-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
2	प्रशासकीय विभाग मॉड्यूल- न मांग, न जांच, न घटना प्रमाण-पत्र जारी करना।	नियुक्तकर्ता अधिकारी शासन की दशा में न मांग, न जांच, न घटना संबंधी प्रस्ताव अधीनस्थ विभागाध्यक्ष से ऑनलाईन प्राप्त कर प्रमाण-पत्र अधीनस्थ विभागाध्यक्ष, संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक को ऑनलाईन प्रेषित करना।	अधीनस्थ विभागाध्यक्ष से प्रस्ताव ऑनलाईन प्राप्त करने के 15 कार्य दिवस के भीतर।
3	विभागाध्यक्ष मॉड्यूल- न मांग, न जांच, न घटना प्रमाण-पत्र जारी करना।	नियुक्तकर्ता अधिकारी विभागाध्यक्ष होने की दशा में न मांग, न जांच, न घटना संबंधी प्रस्ताव अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख से प्राप्त कर प्रमाण-पत्र अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख एवं संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक को ऑनलाईन प्रेषित करना।	अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख से प्रस्ताव ऑनलाईन प्राप्त करने के 15 कार्य दिवस के भीतर।
		नियुक्तकर्ता शासन होने की दशा में न मांग, न जांच, न घटना जारी संबंधी प्रस्ताव अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख से ऑनलाईन प्राप्त कर संबंधित प्रशासकीय विभाग को ऑनलाईन प्रेषित करना।	प्रस्ताव ऑनलाईन प्राप्त करने के 7 कार्य दिवस के भीतर।

3/ सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 20-1/2017/1/3, दिनांक 26.04.2017 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिलिपि संलग्न है) द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा रिट पिटिशन (एस) क्र. 5256/2016- श्याम देव विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2017 की कंडिका 14 (iii) में दिये गये

निर्देशों के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 20-1/2017/1/3, दिनांक 26.04.2017 द्वारा सभी विभागों में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संबंधित विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक पालन कराना सुनिश्चित करें ताकि सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों/सेवाकाल के दौरान दिवंगत शासकीय सेवकों के देय स्वत्वों का समय पर भुगतान/निराकरण हो सके।

4. पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा के अनुसार न मांग प्रमाण-पत्र तथा न जांच प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में समस्त प्रशासकीय विभागों, विभागाध्यक्षों और नियुक्तकर्ता प्राधिकारियों (जैसी भी स्थिति हो) सुनिश्चित करें कि न मांग प्रमाण-पत्र तथा न जांच प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी आवश्यक/निर्धारित कार्यवाही को उच्च प्राथमिकता दी जाये ताकि सेवानिवृत्ति की तिथि की न मांग अथवा न जांच प्रमाण-पत्र संबंधित कर्मचारी को निर्धारित समयावधि अनुसार प्राप्त हो जाये।

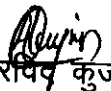
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(अलरमेल मंगई डी.)  
सचिव

//4//

पृ.क्र.115/एफ 2019-55-00016 / वि/नि/चार/2020, नवा रायपुर अटल नगर दि.11/2/2021  
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
  2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
  3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर
  4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
  5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
  6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
  7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
  8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
  9. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
  10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
  11. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
  12. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
  13. समस्त अपर सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
  14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
  15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
  16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
  17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
  18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
  19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
  20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
  21. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु

  
(अरुण कुमार)  
अवर सचिव

दूरभाष क्र. 0771-2510892

राज्य प्रवेश शासन  
वित्त विभाग  
भंगलपुर  
===

क्रमांक बी. 25/26/97/पोडडल्यूसी/धार,

मो गल, दिनांक 12/12/97

त,

- (1) शासन के सभ्य विभाग,
- (2) अध्यक्ष, राजस्व मंडल, गवा नियर,
- (3) एनस्ट संभागीय कमिन्तर,
- (4) एनस्ट विभागाध्यक्ष,
- (5) सभ्यता कलेक्टर,

भंगलपुर ।  
=====

विषय:- सेवा निवृत्ति के प्रकरणों में न मांग प्रमाण पत्र तथा न जांच प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में ।

संदर्भ :- इस विभाग का आप क्रमांक बी. 25/20/94/पोडडल्यूसी/धार, दिनांक 30.5.97 ।  
=====

विध्यांतर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्र का ध्यान अवलोकन करें ।

2/ राज्य शासन द्वारा उपरोक्त विषय में मध्य-मगध पर कई निर्देश प्रसारित किये गये हैं, जिनका उद्देश्य यह था कि, इन निर्देशों के श्रुत्य कार्यवाही कर सेवा-निवृत्त शासकीय सेवाओं को शीघ्रता से न मांग एवं न जांच प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके और उसे जो गलतियों से वेंगल पारलाओं के भुक्तान में तिलंब न हो । परन्तु यह देखने में आया है कि शासन द्वारा जारी विस्तृत एवं दृष्टाष्ट निर्देशों के बावजूद अनेक प्रकरणों में न मांग एवं न जांच प्रमाण पत्र को प्राप्त करने में वेंगल भी को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । प्रायः यह देखा गया है कि कार्यालय प्रमुख द्वारा इन प्रमाण पत्रों के संबंध में सभ्य पर कार्यवाही नहीं की जाती और उदासीनतापूर्वक वेंगल संबंधी अभिलेख अंतिम निराकरण के लिये भेज दिये जाते हैं । इसी तरह से भंगलक, संयुक्त भंगलको, जोध लेखा एवं वेंगल द्वारा सेवा निवृत्त कार्यालयियों के प्रकरणों, जिनके विस्तृत न तो न्यायिक और न ही विभागीय कार्यवाही ग्रथ है, के वेंगल प्राधिकार पत्रों पर न मांग प्रमाण पत्र एवं न जांच प्रमाण पत्र कोपालक में प्रस्तुत करने पर भुक्तान को

148

अंतर्गत अंकित की जाती है।

3/ अतः इस संबंध में कार्यालय प्रमुख के स्तर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विरुद्ध न मांग तथा न जांच प्रमाण-पत्र के संबंध में इस प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे कि पेंशन प्रकरण के साथ ही न मांग एवं न जांच प्रमाण-पत्र संलग्न कर पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिये प्रकरण संशुद्ध संचालित होय, लेखा एवं पेंशन को भेजा जाय।

4/ जिन कर्मचारियों के सेवा संदर्भ का नियंत्रण विभागाध्यक्ष अथवा प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जाता है, उनके मामले में समाप्त पर न मांग प्रमाण-पत्र एवं न जांच प्रमाण-पत्र जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष अथवा प्रशासकीय विभाग की होगी। प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया सुनिश्चित की जावे कि सेवानिवृत्ति की तिथि को न मांग अथवा न जांच प्रमाण-पत्र संबंधित कर्मचारी को मिल जाय।

5/ राज्य शासन चाहता है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

*M. N. Kar*

मिलिन्द वाईकर  
राज्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठ/बी. 25/25/97/पीडब्ल्यूसी/चार, भोपाल, दिनांक 12/12/97

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव भोपाल.
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर.
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.

धारी  
वाही  
ण-  
धालक

ना  
ण  
भण्य  
क्ष  
तेशि

ग  
37

- 6. अवसर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना शाखा, भोपाल.
- 7. अवसर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण शाखा, भोपाल.
- 8. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल.
- 9. प्रांताध्या, म०प्र०तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, 89/61, तुलसी नगर, भोपाल.
- 10. प्रांताध्या, म०प्र०राजपट्टि अधिकारी संघ, 110/10, गिताजी नगर, भोपाल.
- 11. प्रांताध्या, म०प्र०लघुवेतन कर्मचारी संघ, 12/5, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल.
- 12. प्रांतीय प्रमुख महामंत्री, म०प्र०शिक्षक कॉग्रेस ई-6/45 बंगले, नार्थ टी.टी. नगर, भोपाल.
- 13. प्रांताध्या, म०प्र०शिक्षक संघ, कार्यालय, 69/1, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल.
- 14. महामंत्री, म०प्र०राज्य कर्मचारी संघ, 43/26, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल.
- 15. प्रांताध्या, म०प्र०कर्मचारी कॉग्रेस, 98/43, तुलसी नगर, भोपाल.
- 16. प्रांतीय महामंत्री, म०प्र०अनुजाति/जनजाति, अधिकांशी 2 कर्मचारी संघ, 83/05, तुलसी नगर, भोपाल.
- 17. अध्या, म०प्र०मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन, भोपाल.
- 18. पेंशनर कल्याण मंडल के सभी सदस्य.
- 19. महालेखाकार, लेखा एवं इकदाती, आडिट, 1/2, मध्यप्रदेश, गतातिवर, भोपाल.
- 20. सभी संग्रहीत संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं धन, मध्यप्रदेश.
- 21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाखा, मध्यप्रदेश.
- 22. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश.

*(Signature)*

सिद्धि चंद्र शर्मा  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 245/एल 2018-55-00002/वि/नि/चार  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 23 मई, 2018

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़.

विषय:-राज्य के पेंशनरों हेतु 'ऑन लाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम' - "आमार - आपकी सेवाओं का" लागू करने के संबंध में।

राज्य शासन के कर्मचारियों को निम्न नियमों के अंतर्गत पेंशन, उपदान एवं पेंशन सारांशीकरण की पात्रता है :-

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976
  2. छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी (पेंशन) नियम, 1979
  3. पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार पेंशन नियम, 1965
  4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (असाधारण) पेंशन नियम, 1963
  5. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन का कम्प्यूटेशन) नियम, 1996
- (2) वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत पेंशन स्वीकृति हेतु कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पेंशन स्वीकृति का प्रस्ताव सहपत्रों सहित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को प्रेषित किया जाता है। संयुक्त संचालक द्वारा परीक्षण उपरांत प्रकरण सही पाये जाने पर पेंशन भुगतान आदेश (PPO), उपदान भुगतान आदेश (GPO) तथा सारांशीकरण भुगतान आदेश (CPO) जारी किया जाता है, तदोपरांत कोषालय अधिकारी पेंशनर के सत्यापन उपरांत प्रथम भुगतान करते हुए आगामी अवधि के भुगतान हेतु पेंशनर द्वारा आवेदित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को प्रकरण स्थानांतरित करता है।





- (3) उक्त प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब एवं विभिन्न स्तर पर होने वाली कागजी कार्यवाहियों को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त नियमों के अंतर्गत 31 मई, 2018 से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनरों के पेंशन एवं पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान 'आनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम' - 'आभार - आपकी सेवाओं का' के माध्यम से किया जाए।
- (4) इस सिस्टम में सात माड्यूल होंगे, जो एकीकृत रूप से निम्नानुसार कार्य संपादित करेंगे -

स. कं.	माड्यूल का नाम एवं मुख्य कार्य	कार्य का विवरण	समय-सीमा
1	कार्यालय प्रमुख माड्यूल-स्वीकृतकर्ता अधिकारी के रूप में पेंशन प्रकरण संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय को प्रेषित करना।	<p>1/- वित्त विभाग की पेंशन मैनेजमेंट वेबसाइट <a href="http://www.ekoshonline.cg.nic.in/Aabhar">www.ekoshonline.cg.nic.in/Aabhar</a> पर संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा प्रदाय यूजर नेम एवं पासवर्ड से login करना।</p> <p>2/- सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, विभागीय विवरण, गणना विवरण एवं दस्तावेज विवरण की प्रविष्टि करना।</p> <p>3/- वांछित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करना।</p> <p>4/- समस्त प्रकार के संभावित आपत्तियों को चेक लिस्ट के माध्यम से दूर करना।</p> <p>5/- सुरक्षित किये गये पेंशन प्रपत्र download एवं अभिप्रमाणन कर भौतिक रूप से सेवा पुस्तिका के साथ संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय को प्रेषण।</p> <p>6/- e-ppo/e-gpo/e-cpo जारी होने के पश्चात् वांछित दस्तावेज कोषालय अधिकारी को ऑन लाईन प्रेषित करना।</p>	<p>बिन्दु क्रमांक 01 से 05 हेतु- (i)पेंशन प्रकरण बनाने का कार्य पूर्व की भांति 24 माह पहले से प्रारम्भ किया जाएगा।</p> <p>(ii)सेवानिवृत्ति की तिथि से 03 माह पूर्व पेंशन प्रकरण ऑनलाईन प्रेषित करना अनिवार्य होगा।</p> <p>(iii)पेंशन प्रकरण समय पर प्रेषित करने की जवाबदेही कार्यालय प्रमुख की होगी।</p> <p>(iv)संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा ऑनलाईन आपत्ति सहित पेंशन प्रकरण वापस करने पर इसका निराकरण 15 कार्य दिवस में किया जाना अनिवार्य होगा।</p> <p>6/- e-ppo/e-gpo/e-cpo प्राप्त होने से 07 कार्य दिवस</p>
2	प्रशासकीय विभाग माड्यूल- न मांग, न जांच, न घटना प्रमाण-पत्र जारी करना।	<p>1/- वित्त विभाग की पेंशन मैनेजमेंट वेबसाइट <a href="http://www.ekoshonline.cg.nic.in/Aabhar">www.ekoshonline.cg.nic.in/Aabhar</a> पर संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा प्रदाय यूजर नेम एवं पासवर्ड से login करना।</p>	1/- निरंक

		2/-नियुक्तकर्ता अधिकारी शासन की दशा में न मांग, न जांच, न घटना संबंधी प्रस्ताव अधीनस्थ विभागाध्यक्ष से ऑनलाईन प्राप्त कर प्रमाण-पत्र अधीनस्थ विभागाध्यक्ष, संबंधित कार्यालय प्रमुख एवं संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक को ऑनलाईन प्रेषित करना ।	2/- अधीनस्थ विभागाध्यक्ष से प्रस्ताव ऑनलाईन प्राप्त करने के 15 कार्य दिवस के भीतर ।
3	विभागाध्यक्ष मॉड्यूल- न मांग, न जांच, न घटना प्रमाण पत्र जारी करना ।	1/- वित्त विभाग की पेंशन मैनेजमेंट वेबसाईट <a href="http://www.ekoshonline.cg.nic.in/Aabhar">www.ekoshonline.cg.nic.in/Aabhar</a> पर संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा प्रदाय यूजर नेम एवं पासवर्ड से login करना । 2/-नियुक्तकर्ता अधिकारी विभागाध्यक्ष होने की दशा में न मांग, न जांच, न घटना संबंधी प्रस्ताव अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख से प्राप्त कर प्रमाण-पत्र अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख एवं संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक को ऑनलाईन प्रेषित करना । 3/-नियुक्तकर्ता शासन होने की दशा में न मांग, न जांच, न घटना जारी संबंधी प्रस्ताव अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख से ऑनलाईन प्राप्त कर संबंधित प्रशासकीय विभाग को ऑनलाईन प्रेषित करना ।	1/- निरंक  2/- अधीनस्थ कार्यालय प्रमुख से प्रस्ताव ऑनलाईन प्राप्त करने के 15 कार्य दिवस के भीतर ।  3/-प्रस्ताव ऑनलाईन प्राप्त करने के 07 कार्य दिवस के भीतर ।
4	संभागीय संयुक्त संचालक मॉड्यूल-स्वीकृतकर्ता अधिकारी के प्रस्ताव को ऑडिट ऑफिसर के रूप में परीक्षण करना एवं e-ppo/e-gpo/e-cpo जारी करना ।	1/- वित्त विभाग की पेंशन मैनेजमेंट वेबसाईट <a href="http://www.ekoshonline.cg.nic.in/Aabhar">www.ekoshonline.cg.nic.in/Aabhar</a> पर संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा प्रदाय यूजर नेम एवं पासवर्ड से login करना । 2/- कार्यालय प्रमुख द्वारा ऑनलाइन भरी गयी जानकारियों तथा भौतिक रूप से प्राप्त अभिप्रमाणित पेंशन प्रपत्र एवं सर्विस बुक का परीक्षण करना । 3/-ऑनलाईन भरी जानकारी एवं सर्विस बुक में भरी जानकारी में मिल्नता होने पर सर्विस बुक में भरी जानकारी को मान्यता प्रदान करना । 4/-प्राप्त प्रकरण को सेवानिवृत्ति तिथि तक डिजीटल हस्ताक्षर युक्त e-ppo/e-gpo/e-cpo कोषालय अधिकारी को ऑनलाईन जारी करना एवं कार्यालय प्रमुख को ऑनलाईन तथा पेंशनर्स को ई-मेल के	1/- निरंक  2, 3 एवं 4 हेतु/- सर्विस बुक एवं अभिप्रमाणित पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने के एक माह के भीतर । डिजीटल हस्ताक्षर युक्त e-ppo/e-gpo/e-cpo का नवीन प्रारूप प्रपत्र परिशिष्ट 01, 02 एवं 03 संलग्न है ।

A


		माध्यम से कवरिंग लेटर स्वतः प्रेषित करना। महालेखाकार कार्यालय एवं पेंशनर्स को कवरिंग लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना।	
5	कोषालय अधिकारी मॉड्यूल- पेंशनर को प्रथम पेंशन, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान एवं सारांशिकरण साशि जारी करना।	1/-संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जारी e-ppo/e-gpo/e-cpo को ऑनलाईन प्राप्त कर आवश्यक अभिलेख हेतु कार्यालय प्रमुख को ऑनलाईन निवेदन करना। 2/-कार्यालय प्रमुख से अपेक्षित अभिलेख ऑनलाईन प्राप्त होते ही ई-देयक तैयार कर भुगतान की कार्यवाही किया जाना। 3/-पेंशनर का कोषालय में स्वयं के सत्यापन हेतु उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त किया जाना। 4/-भुगतान के पश्चात स्वतः पेंशनर द्वारा चयन किये गये बैंक में आगामी पेंशन भुगतान हेतु नोडल बैंक को डिजीटल हस्ताक्षर युक्त ई-पीपीओओ, एक्स.एम.एल. फाईल एवं वांछित अभिलेख ऑनलाईन प्रेषित करना।	1/- 03 कार्य दिवस  2/- e-gpo/e-cpo का भुगतान 7 कार्य दिवस तथा पेंशन का भुगतान आगामी देय तिथि। 3/- निरंक  4/- निरंक
6	बैंक मॉड्यूल- पेंशनर को आगामी पेंशन का भुगतान करना	1/-बैंक द्वारा ई-पीपीओओ एवं एक्स.एम.एल. फाईल ऑन लाईन प्राप्त होने पर भुगतान। 2/-बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को भुगतान करने के पश्चात् एम.आई.एस साईबर ट्रेजरी से शेरर करना।	1/- आगामी देय तिथि  2/- भुगतान तिथि के 01 कार्य दिवस पश्चात्
7	डीटीएपी मॉड्यूल-समन्वय एवं नियंत्रण	1/-विभिन्न मॉड्यूल के मध्य नियन्त्रण तथा समन्वय स्थापित करना है। 2/-शासन द्वारा समय-समय पर जारी पेंशन संबंधित दिशा-निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करना। 3/-पेंशन शिकायत निवारण प्रणाली अंतर्गत शिकायत निवारण। 4/-पेंशन डाटा बेस 5/-वेबसाईट का परिचालन 6/-पेंशनर हेतु मोबाईल ऐप का परिचालन	1/- निरंक  2/- तत्समय  3/- 15 कार्य दिवस  4/- निरंक 5/- निरंक 6/- निरंक

(5) उक्त प्रणाली के लागू होने के फलस्वरूप कोषालय संहिता एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा छत्तीसगढ़ शासन सिविल पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान की योजना में समुचित संशोधन अलग से किया जायेगा। उक्त संशोधन होने तक उपरोक्त नियम एवं योजना पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम की सीमा तक शिथिल माने जायेंगे।

- (6) पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक ई-4/3, 86/R-V/IV दिनांक 21.4.86 द्वारा लागू पेंशन की विभागीयकरण योजना की कंडिका-16 के प्रावधानानुसार प्रत्येक पीपीओ, जीपीओ, सीपीओ में एम्बॉसिंग सील लगाने की व्यवस्था समाप्त हो जायेगी तथा संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा जारी किये जाने वाले समस्त ई-पीपीओ, ई-जीपीओ तथा ई-सीपीओ संयुक्त संचालक के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी होंगे।
- (7) राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में राज्य के समस्त वर्तमान पेंशन भोगियों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जायेगा जिसके अंतर्गत वर्तमान पेंशनरों के अब तक किये गये भुगतान एवं भविष्य में किये जाने वाले भुगतानों एवं संशोधनों का अनुश्रवण हो सके।
- (8) पेंशन भुगतान की उक्त व्यवस्था कंडिका-1 में उल्लेखित पेंशन नियमों के अतिरिक्त किसी अन्य निर्देशों/विधियों के अंतर्गत स्वीकृत पेंशन हेतु लागू नहीं होगी।
- (9) पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने एवं इसके संचालन हेतु संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(अमिताभ जैन)  
प्रमुख सचिव  
23/5/18

पृ. क्र. 246/एल 2018-55-00002/वि/नि/चार  
प्रतिलिपि,

नया रायपुर, दिनांक 23 मई, 2018

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर  
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) पर अपलोड करने हेतु

  
(अतुल कुलश्रेष्ठ)  
शोध अधिकारी

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन संभाग, (छत्तीसगढ़)

जावक क्रमांक / - / पी-ए- / / E

दिनांक

पेंशन अदायगी आदेश  
संवितरक / पेंशनर का भाग

पी.पी.ओ. क्र.

छत्तीसगढ़ शासन को विकसनीय

मुख्य शीर्ष - 2071 पेंशन

उप-शीर्ष (स्तद्वय/भाषित)

मूल पेंशन -

सारणीकृत पेंशन -

1. सेवा में प्रवेश की तिथि	
2. कुल सेवा	वर्ष/माह/दिन
3. अंतिम / औसत उपलब्धि	

अनुसूची

शेषद्वय पेंशन -

पेंशनर का नाम तथा सेवानिवृत्ति/निधन की तिथि	पेंशन का वर्ग तथा प्रारंभ होने की तिथि	कद तथा वैयक्तिक पहचान के निशान	जन्म तिथि	धर्म और राष्ट्रीयता	पेंशनर का पूरा पता	पेंशन की मासिक राशि	वेतनमान जिसके अनुसार मेंहगाई राहत देव
1	2	3	4	5	6	7	8
		सैंभी					

प्रति,

जिला कोषालय अधिकारी,

कृपया ऊपर दी गई अनुसूची के अनुसार श्री/श्रीमती/कु सेवानिवृत्ति(पद) कार्यालय को आगामी सुचना तक और हर माह के समाप्त होने पर मूल पेंशन के रूप में राशि ₹ (शब्दों में ₹) में से सारणीकृत पेंशन राशि ₹ (शब्दों में ₹) को घटाकर शेष पेंशन राशि ₹ (शब्दों में ₹) तथा राहत के अनुसार मूल पेंशन ₹ पर दिनांक से प्रति माह उनकी मृत्यु अथवा 15 वर्ष पूर्ण होने तक देय होगा। तत्परन्तु नियमानुसार मूल पेंशन राशि ₹ (शब्दों में ₹) भुगतान योग्य होगा

- मृत्यु सहसेवानिवृत्ति उपपदान प्राधिकार क्र. वास्ते ₹ (शब्दों में ₹.)

- संराशिकरण राशि ₹ (शब्दों में ₹)

- भुगतान के समय पूर्व में भुगतान की गई प्रत्याशित पेंशन तथा पेंशन से बसूली योग्य राशियों का सम्बन्धजन करें तथा कार्यालय प्रमुख से आवश्यक दस्तावेज भी प्राप्त करें।

विभाजन योग्य				
	वर्धित दर	सामान्य दर	उपदान	संराशिकरण
एकीकृत म.प्र.				
म.प्र.				
छ.ग.				
योग				

संभागीय संयुक्त संचालक  
कोष लेखा एवं पेंशन  
संभाग (छत्तीसगढ़)

A

शोध अधिकारी

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन संभाग, (छत्तीसगढ़)

जावक क्रमांक / - / पी-ए- / / E

प्रति,  
जिला कोषालय अधिकारी

दिनांक

दिनांक	
विभाजन योग्य	
एकीकृत मध्यप्रदेश रुपये	
मध्यप्रदेश रुपये	
छत्तीसगढ़ रुपये	
योग	

G.P.O.No.  
UNDER RS.

विषय : मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान प्राधिकार-पत्र।

श्री/श्रीमती/कु- सेवानिवृत्ति(पद) कार्यालय

के हित में संस्वीकृत मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान राशि (शब्दों में ₹ )

उपादान ग्राही श्री/श्रीमती/कु-

अथवा नाबालिगों के नीचे उल्लेखित कानूनी अभिभावक को नीचे पैरा-2 में उल्लेखित वसूलियाँ काटकर अदा करें।

2. ऊपर प्राधिकृत उपादान अदायगी में से नीचे की राशि का सम्भोजन करें।

I प्रत्याशित पेंशन / उपादान की राशि का सम्भोजन करें।

II लोक निर्माण विभाग/विभाग से शासकीय आवास का किराया बकाया न होने एवं आवास रिक्त होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।

III अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र राशि ₹ दिनांक तक भुगतान दर्शाते हुए प्राप्त करें।

IV अधिक भुगतान की राशि ₹ (शब्दों में) की वसूली की जाये।

V.....

3. आदात को इस आदेश के जारी होने की सूचना दे देनी चाहिए।

4. उपादान ग्राही/कानूनी अभिभावक के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगुठों और अंगुलियों के छाप की पर्तियाँ और उनके फोटो की प्रमाणित प्रति इसके साथ भेजी जा रही है कार्यालय के पत्र क्रमांक विभाग दिनांक के साथ भेजे गए पेंशन के साथ सलन कर आपको भेजी जा चुकी है।

5. उपादान की राशि मांग संख्या - 08 - सीई - 2071 - पेंशन और सेवानिवृत्ति लाम - (01) - सिविल - (104) - उपादान को विकलित हो जाये।

6. उपादान आदेश में दर्शायी गयी वसूलियाँ, उनके स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित विभाग या वित्त विभाग के संबंधित लेखा शीर्ष में क्लान द्राफ्ट जमा (क्रेडिट) की जाये।

7. अदायगी के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उपादानग्राही अब भी इसका अधिकारी है यदि नहीं तो इसे वापस करें।

8. उपादान के भुगतान होने तक यह प्राधिकार पत्र संवितरण अधिकारी के वैयक्तिक अभिरक्षण में रखा जाना चाहिये। यह प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख से केवल 12 माह तक के लिए प्रभावी रहेगा। यदि इस अवधि में कोई अदायगी न की गई हो तो इसे निरस्त (निष्प्रभावी) माना जाये और इस कार्यालय को लौटा दिया जाना चाहिये।

9. स्मरण रहे कि संवितरण अधिकारी, आदाता, जिसका पत्र नीचे दिया गया है की पहचान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

10. पेंशन अदायगी आदेश क्रमांक / सं-सं- / विभाग / कृपया इस पत्र के प्राप्ति की पायती भेजें।

संभागीय संयुक्त संचालक  
कोष, लेखा एवं पेंशन  
संभाग, (छत्तीसगढ़)

जावक क्रमांक / - / पी-ए- / / E

दिनांक

प्रतिलिपि:-

1-श्री/श्रीमती/कु- पेंशन/उपादान भोगी का पत्र

(उपादान ग्राही/कानूनी अभिभावक) को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अधेषित।

टीप- जब तक ग्राही द्वारा किसी ऐसे प्राधिकृत एजेंट के जरिये अदायगी करने की इच्छा व्यक्त न की जाये, जिसने सरकार को अधिकार अदायगी के लिए बलिपूर्ति करने का वचन दे रखा हो।

संभागीय संयुक्त संचालक  
कोष, लेखा एवं पेंशन  
संभाग,

कार्यालय , संभागीय संयुक्त संचालक , कोष लेखा एवं पेंशन संभाग, (छ.ग.)

UNDER RS.

क्रमांक / / सारांसीकरण /E  
प्रति

जिला कोषालय अधिकारी

दिनांक	
विभाजन योग्य	
एकीकृत मध्यप्रदेश	₹
मध्यप्रदेश	₹
छत्तीसगढ़	₹
योग	

**विषय :- पेंशन सारांसीकरण प्राधिकार - पत्र ।**

1. इस कार्यालय के पेंशन अदायगी आदेश क्रमांक / सं.सं./ विभाग/E के धारक श्री /श्रीमती /कु सेवानिवृत्त (पद) कार्यालय को स्वीकृत पेंशन की राशि ₹ ( शब्दों में ₹ ) में से ₹ ( शब्दों में ₹ ) के सारांसीकरण मूल्य (कम्प्यूटेड वैल्यू) ₹ ( शब्दों में ₹ ) के भुगतान की स्वीकृति कार्यालय प्रमुख / वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई है । एतएव , आपसे अनुरोध है कि आवश्यक सत्यापन के परभावत उक्त राशि के भुगतान की व्यवस्था करें , तथा पेंशन का सारांसीकरण मूल्य लेखाशीर्ष - 2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ - (02) पेंशनो का रूपान्तरित मूल्य के अंतर्गत , छत्तीसगढ़ शासन को विकलित करें ।
2. सारांसीकरण के परिणाम स्वरूप पेंशन भोगी द्वारा पेंशन के सारांसीकृत मूल्य की प्राप्ति की तारीख अथवा इस प्राधिकार के जारी करने की तिथि से जिस दिन तीन माह पूर्ण होते है जो भी पहले हो , पेंशन की राशि ₹ ( शब्दों में ₹ ) प्रतिमाह उनकी मृत्यु अथवा 15 वर्ष तक , जो भी पहले हो , तक देय होगी । तत्पश्चात नियमानुसार पुनः पूरी पेंशन राशि ₹ ( शब्दों में ₹ ) निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने पर उनकी मृत्यु तक देय होगी । कृपया इस प्राधिकार पत्र का क्रमांक एवं दिनांक अंकित करते हुए मूल पेंशन की राशि में उपरोक्तानुसार संशोधन करें तथा इस आशय की टीप पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भागों पर देते हुए अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करें ।
3. इस पत्र के क्रमांक एवं दिनांक की प्राधिकार के रूप में सन्दर्भ देते हुए सारांसीकृत राशि के भुगतान के लिए अलग से बिल तैयार किया जावे तथा भुगतान किया हुआ काउचर महालेखाकार , छत्तीसगढ़ , रायपुर को अलग अनुसूची के साथ पंजीकृत ढाक से भेजा जावे । इस काउचर को भेजने सन्बन्धी सूचना इस कार्यालय को भी दी जावे ।
4. इस पत्र की पावती भेजे तथा यह प्रमाणित करें कि पेंशन आदेश की दोनों भागों पर सारांसीकरण के परिणामस्वरूप पेंशन की राशि में हुए परिवर्तनों को लागू कर दिया गया है ।

संभागीय संयुक्त संचालक  
कोष,लेखा एवं पेंशन  
संभाग, (छ.ग.)

पृष्ठा क्रमांक / /  
प्रतिसिफि-

/E

दिनांक

1. श्री / श्रीमति / कु पेंशन भोगी का पता की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अत्रेभित ।

संभागीय संयुक्त संचालक  
कोष,लेखा एवं पेंशन  
संभाग, (छ.ग.)

A



छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 20-1/2017/1/3  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 26/04/2017

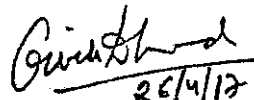
समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/  
सचिव/विशेष सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
समस्त विभाग,  
मंत्रालय, नया रायपुर

विषय :- रिट पिटिशन (एस) क. 5256/2016-श्याम देव विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करना।

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा रिट पिटिशन (एस) क. 5256/2016-श्याम देव विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.2.2017 की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। उक्त आदेश की कंडिका 14(iii) में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 20-1/2017/1/3, दिनांक 26/04/2017 द्वारा सभी विभागों में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उक्त आदेश की छायाप्रति भी सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

2/ कृपया मान. न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आपके विभाग में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक पालन कराना सुनिश्चित करें ताकि सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों/सेवाकाल के दौरान दिवंगत शासकीय सेवकों के देय स्वत्वों का समय पर भुगतान/निराकरण हो सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

  
26/4/17

(विवेक ढांड)

मुख्य सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन,

162  
26/04/17

A. D. R. / 26/4/17

AFR

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

W.P. (S) No. 5256 of 2016

Shyam Dev, son of Mansai, husband of late Silbina Lakra,  
aged about 68 years, resident of Village-Kamalpur, Tahsil-  
Kusmi, District Balrampur-Ramanujganj (C.G.)

---- Petitioner

Versus

1. State of Chhattisgarh, Through Secretary, Health & Family Welfare Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, New Raipur, Distt. Raipur (C.G.)
2. The Director, Health Services, Raipur, District Raipur (C.G.)
3. The Chief Medical & Health Officer, District Chikitsalaya, Ambikapur, District Surguja (C.G.)
4. The Block Medical Officer, Kusmi, District Balrampur-Ramanujganj (C.G.)
5. The Accountant General, Chhattisgarh, Raipur (C.G.)
6. The Joint Director, Treasury, Accounts & Pension, Bilaspur (C.G.)

— Respondents

---

For Petitioner : Mr. G.P. Vishwakarma,  
Advocate.  
For Respondents No.1 to 4 & 6 : Mr. Dhiraj Kumar Wankhede, GA  
For Respondent No. 5 : Mr. Raj Kumar Gupta, Advocate.

Dr. N.K. Pandey, Chief Medical & Health Officer, Ambikapur  
Mr. A.K. Pandey, Joint Director, Treasury, Accounts & Pension,  
Bilaspur are present in person.

---

Hon'ble Shri Justice Sanjay K. Agrawal

Order On Board

17/02/2017

(1) "In case of an employee retiring after having rendered the services, it is expected that all the payments of retiral benefits should be paid on the date of retirement or soon thereafter if for some unforeseen circumstances the payment could not be made on the date of retirement"

(2) The afore-stated mandate of the Supreme Court rendered in the matter of *Vijay L. Mehrotra Vs. State of U.P. & others*<sup>1</sup> has been observed by the authorities of the State Government in the present case in its breach. In the instant case most of the payment of retiral benefits were paid to petitioner long after the petitioner's wife, who was government servant died on 7.2.1999 and even the amount of General Provident Fund has not been paid yet.

(3) The Essential facts to demonstrate the above-stated callousness on the part of the State Authorities in making payment of retiral dues to the petitioner are as under:-

(i) Smt. Silbina Lakra (petitioner's wife) was appointed as Auxiliary Nurse Midwifery in the Community Health Centre on 21.11.1968. She suffered paralytic attack and ultimately died on 7.2.1999 and on account of paralysis she could not attend her duties from 31.07.1991 to 07.02.1999.

(ii) After death of Smt Silbina Lakra, the petitioner made an application for grant of admissible retiral benefits and also made an application for grant of earned leave to her from 31.07.1991 to 07.02.1999 (period of absence).

<sup>1</sup> (2001) 9 SCC 687

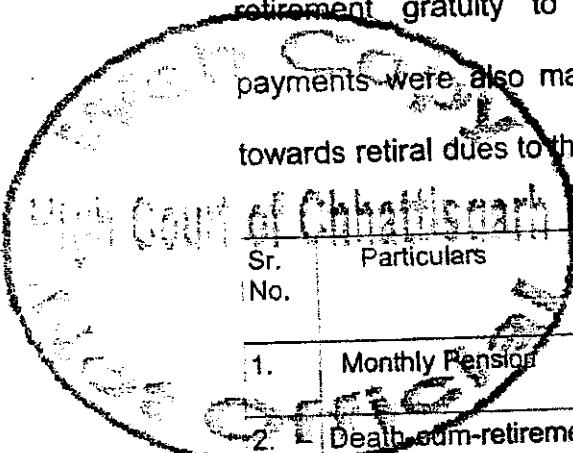
(iii) The said application was sent to respondent No. 6- Joint Director, Treasury, Accounts & Pension, Bilaspur for necessary action, which was returned by respondent No. 6 on 11.10.1999 and, thereafter, again matter was sent by respondent No. 3 – the Chief Medical & Health Officer, Ambikapur to respondent No. 6 stating that period of absence be treated as *dies non*. Again the respondent No. 6 by its letter dated 9.4.2001 raised an objection that the authority for declaring the period of absence as *dies non* vests in the Director, Health Services, therefore, period from 31.7.1991 to 7.2.1999 be declared *dies non* by appropriate competent authority.

(iv) The aforesaid request of Chief Medical & Health Officer was made to the Director, Health Services, Raipur on 9.5.2001. Again the same request were reiterated on 24.09.2004, 17.07.2006 & 17.08.2006 but the Director, Health Services did not take cognizance on the said request (s) and matter remained pending with the Director, Health Services, respondent No. 2 herein with no decision on the matter.

(4) Feeling unhappy with the non-grant of pension & other retiral benefits, the petitioner herein filed a writ petition being Writ Petition (S) No.2170/2011 before this Court for directing the State Government to disburse the retiral benefits to the petitioner and for direction to the Director (Health Services) to decide his matter regarding non-payment of retiral dues and to fix provisional pension. That writ petition was disposed of by this Court on 26<sup>th</sup> April, 2011 on the undertaking of the State Government that the decision would be taken resolving the dispute regarding

petitioner's retiral benefits within a period of eight weeks in accordance with law.

(5) Pursuant to the order of this Court dated 26.04.2011, the respondent No. 2 – Director, Health Services, Raipur by its order dated 27.07.2011, declared the period of absence of petitioner's wife as *dies non*. Thereafter, the Joint Director, Treasury, Accounts & Pension, Ambikapur, by its order dated 28.10.2011 passed an order granting monthly pension & death-cum-retirement gratuity to the petitioner and, thereafter some payments were also made. The details of the payments made towards retiral dues to the petitioner till this date are as under:-



Sr. No.	Particulars	Amount paid	Date
1.	Monthly Pension	Rs.1,973 + D.A.	28.10.2011
2.	Death-cum-retirement gratuity	Rs.24,768/-	28.10.2011
3.	Leave encashment	Rs.14,304/-	15.07.2014
4.	Family Welfare Fund	Rs.9,101/-	03.02.2017
5.	General Insurance Scheme	Rs.17,995/-	03.02.2017
6.	Group Insurance	Rs.1,00,000/-	03.02.2017
7.	GPF amount	Nil	Nil Proposal was sent on 7.1.2017 to Accountant General

(6) Grant of retirement benefits including pension, death-cum-

retirement gratuity, and family pension to the government servant are governed by the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976 (hereinafter called as " the Rules of 1976). Rule 43 of the Rules of 1976 provides for amount of pension. Rule 44 of the Rules of 1976 provides for death-cum-retirement gratuity to a government servant. Rule 47 provides for contributory family pension. Rule 48 provides for non-contributory family pension to a government servant.

(6.1) Chapter-VIII of the Rules of 1976 deals with application for and sanction of pension. Rule 49, Rule 57, Rule, 58 Rule 59, Rule 60, Rule 61 and Rule 63 provide for government servant due for retirement.

(6.2) A studied perusal of the aforesaid Rules would show that it is statutory duty of every head of the department/head of the office to prepare a list in every six months i.e. on the 1<sup>st</sup> January and 1<sup>st</sup> July, each year the list of all gazetted and non-gazetted government servants who are due to retire under his order within next 24 to 30 months of that day and thereafter send the copies to the officers mentioned in sub-rules (2) & (4) of Rule 49 of Rules of 1976 for necessary verification. Rule 57(1) of the Rules of 1976 obliges the head of office to undertake the work of preparing pension papers in Form-VI two years before the date on which a government servant is due to retire on superannuation. By virtue

of Rule 58 the head of office shall verify the service records of the government servant and further undertake the formalities mentioned in sub-rules (2) & (3) and thereafter on completion of 13 months before the date of retirement, the head of office shall take up the actual work of preparation of pension papers in Part-I and Part-II of Form-VI and thereafter the head of office shall send Form-VI to the audit officer twelve months before the date of retirement with a covering memo in Form-VII along with service book, service roll duly completed and up to date under Rule 59 of the Rules of 1976. Thereafter the head of office has to take steps for sanction and disbursement of anticipatory pension and gratuity as provided in Rule 61 of the Rules of 1976. Under Rule 63, on receipt of pension papers as provided in Rule 59 the audit officer shall apply the requisite checks and assess the amount of final pension and gratuity not later than two months in advance of the date of retirement and if the audit officer is unable to assess the amount aforesaid, he shall communicate the fact to the head of office. Thus, the payment of pension shall be effective from the date the government servant ceased to be born on establishment, and as such the government servant retiring is entitled to get the amount of pension from the date of his or her superannuation.

(6.3) The rules also prescribe procedure for recovery and adjustment of the government dues. Rule 65 (1) provides that it shall be the duty of every retiring government servant to clear all

government dues before the date of retirement and procedure for recovery of the said dues has been given in sub-rule (2) of Rule 65. Thus, Rule 66 clearly provides that if the retiring government servant furnishes surety as prescribed in Rule 66(1) (a) the grant of pension and gratuity shall not be delayed.

(6.4) Likewise, Chapter-IX of the Rules provides for sanction of family pension and death-cum-retirement gratuity in respect of government servant dying while in service. Detail procedure has been prescribed in Rules 69 and 70 of the Rules of 1976 for payment of retiral dues. The said rules which are applicable to the present case are as under:-

**69. [Payment of family pension and anticipatory family pension and death-cum-retirement gratuity when Government servant dies when in service]** Where the Head of Office has received an intimation about the death of a Government servant while in service, he shall ascertain whether any death-cum-retirement gratuity or family pension or both is or are payable in respect of the deceased Government servant.

(2) (a) Where the death-cum-retirement gratuity under Rule 44, is payable the Head of Office shall ascertain :-

(i) If the deceased Government servant had nominated any person or persons to receive the gratuity; and

(ii) Where the deceased Government servant had not made any nomination or the nomination made does not subsist, the person or persons to whom the gratuity may be payable.

(b) The Head of Office shall, then address the person concerned if Form 9 or Form 10 as may be



appropriate who may submit a claim in Form 11.

(3) Where the family of the deceased Government servant is eligible for the contributory family pension under Rule 47,-

(a) the Head of Office shall address the widow or widower in Form 12 for making a claim in Form 13; and

(b) Where the deceased Government servant is survived only by child or children, the guardian of such child or children may submit a claim in Form 13 to the Head of Office:

Provided that the guardian shall not be required to submit a claim in the said Form on behalf of the unmarried daughter if she has attained the age of eighteen years and such daughter may herself submit a claim in the said Form 13.

(4) (a) Where the family of the deceased Government servant is eligible for non-contributory family pension under Rule 48 of the Head of Office shall ascertain,-

(i) if the deceased Government servant had nominated any member of his family to receive the payment of non-contributory family pension; and

(ii) where the deceased Government servant had not made any nomination or the nomination made does not subsist, the person to whom the non-contributory family pension may be payable.

(b) The Head of Office shall, then, address the person concerned in Form 14 or Form 15 as may be appropriate for making a claim in Form 16.

(5) The Head of Office shall furnish to the Audit Officer the following particulars regarding the details of Government dues outstanding against the deceased Government servant namely:-

(a) Government dues recoverable out of the gratuity before payment is authorised, that is to say :-

(i) contribution towards contributory family pension, if applicable;

- (ii) Government dues which have been ascertained and assessed;
- (b) Amount of gratuity to be held over the adjustment of Government dues which have not been assessed so far.

**Note.-** The amount of gratuity to be held over shall be determined in accordance with the provisions of clauses (b) and (c) of sub-rule (2) of Rule 66.

[(a)] After completing Form 17 the Head of Office shall send that Form in original to the Audit Officer with a covering letter in Form 18 alongwith the Government servant's service book/service roll, duly completed upto date and any other documents relied upon for the verification of the service claimed in such a manner that they can be conveniently consulted.

[(b)] The Head of office shall retain one copy of the aforesaid Form for his office record.

[(c)] If the payment is desired in another circle of audit, Form 17 shall be sent in duplicate to the Audit Officer.

(7) After the documents referred to in sub-rules (5) and (6) have been sent to the Audit Officer concerned, the Head of Office shall draw anticipatory family pension not exceeding the maximum family pension and 90% of the gratuity as indicated in Part I of Form 17 and for this purpose adopt the following procedure namely:-

- (a) he shall issue a sanction letter in favour of the claimant or claimants endorsing a copy thereof to the Audit Officer indicating the amount of anticipatory family pension and 90% of the gratuity payable under these rules;
- (b) he shall indicate in the sanction letter the amount recoverable out of the gratuity under sub-rule (5);
- (c) after issue of the sanction letter, he shall draw-
- (i) the amount of anticipatory pension;

and

(ii) the amount of 90% of the gratuity after deducting therefrom the dues mentioned in clause (b);

from the Treasury at which the pay and allowances of the establishment are drawn by him.

(8) The Head of Office shall disburse the anticipatory family pension and gratuity to the claimant or claimants on or after the first day of the month following the month in which the Government servant died, if final P.P.O./G.P.O. is not received by that time.

(9) The Head of Office shall inform the Audit Officer as soon as the gratuity has been paid to the claimant or claimants with all details of the amount recovered from such gratuity.

(10) If the claimant desires the payment of anticipatory family pension or of gratuity or of both through money order the same shall be remitted to him through money order at the cost of State Government, if the amount is Rs.100 or less.

**70. Authorisation of final family pension and balance of gratuity in respect of a deceased non-gazetted Government servant referred to in Rule 69.** (1) On receipt of the documents referred to in sub-rules (5) and (6) of Rule 69 the Audit Officer shall within a period of six months from the date of death of the Government servant, apply the requisite checks, record his audit enforcement on Section 1 of Part IV of Form 17 and assess the amount of final family pension and gratuity:

Provided that if the Audit Officer is, for any reason, unable to assess the amount within the period aforesaid, he shall communicate the fact to the Head of Office.

(2)(a) If the family pension is payable in his circle of audit, the Audit Officer shall prepare the Pension Payment Order.

(b) The payment of family pension shall be effective from the date following the date on which the Government servant died.

(c) Amount of anticipatory family pension, if any, in respect of the period for which family pension was drawn and disbursed by the Head of Office shall be intimated by the Head of Office to the Treasury Officer concerned and adjusted by him from the final payment of such family pension.

(3)(a) The Audit Officer shall authorise the payment of the gratuity after adjusting the amount, if any, outstanding against the deceased Government servant including the amount of gratuity paid by Head of Office as anticipatory gratuity.

(b) The amount of gratuity held over under sub-rule (5) of Rule 69 shall be adjusted by the Audit Officer against the Government dues ascertained and assessed subsequently and the balance, if any, shall be released to the claimant or claimants after the expiry of the period referred to in clause (a) of sub-rule (3) of Rule 66.

(c) If the gratuity is payable in his circle of audit the Audit Officer shall prepare and issue order for its payment.

(4) The fact of the issue of the Pension Payment Order and order for payment of the gratuity shall be promptly reported to the claimant and Head of Office and the documents which are no longer required shall be returned to him.

(5) The Audit Officer may authorise the payment of gratuity even during the period of the currency of anticipatory family pension:

Provided that the amount of gratuity has been finally assessed and no recovery of Government dues is outstanding against the deceased Government servant.

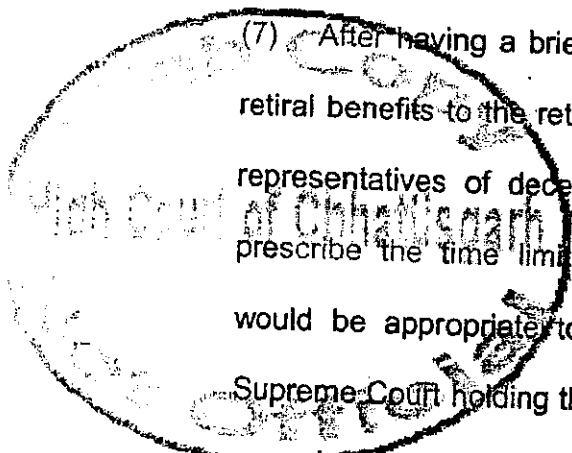
(6) If the final family pension and the gratuity are payable in another circle of audit, the Audit Officer shall send a copy of Form 17 along with the audit encasement and last pay certificate, if received, to the Audit Officer of that circle who shall prepare Pension Payment Order and order for the payment of gratuity:

Provided that the adjustment of anticipatory family pension and gratuity drawn and disbursed by

the Head of Office shall be made by the Audit Officer in whose circle the provisional payments were made.

(7) If the amount of anticipatory family pension drawn and disbursed by the Head of Office is found to be in excess of the final family pension assessed by the Audit Officer, it shall be open to the Audit Officer to adjust the excess amount of the gratuity, if any, or recover the excess amount by short payments of family pension payable in future.

(8) If the amount of gratuity disbursed by the Head of Office proves to be large than the amount finally assessed by the Audit Officer, the gratuitant shall not be required to refund the excess."



(7) After having a brief survey of the Rules governing grant of retiral benefits to the retired government servant and to the legal representatives of deceased government servant which clearly prescribe the time limit for disbursement of retiral benefits, it would be appropriate to notice the relevant judgments of the Supreme Court holding that right to receive pension is recognized as a right to property within the meaning of Article 300A of the Constitution of India.

(7.1) The Constitution Bench of the Supreme Court in the matter of Deokinandan Prasad v. The State of Bihar and others<sup>2</sup> has held that right to receive pension was property under Article 31(1) and Article 19(1)(f) of the Constitution of India and it was held as under:-

"27. The last question to be considered, is, whether the right to receive pension by a government servant is

property, so as to attract Articles 19(1)(f) and 31(1) of the Constitution. This question falls to be decided in order to consider whether the writ petition is maintainable under Article 32. To this aspect, we have already adverted to earlier and we now proceed to consider the same.

33. Having due regard to the above decisions, we are of the opinion that the right of the petitioner to receive pension is property under Article 31(1) and by a mere executive order the State had no power to withhold the same. Similarly, the said claim is also property under Article 19(1)(f) and it is not saved by sub-article (5) of Article 19. Therefore, it follows that the order, dated June 12, 1968, denying the petitioner right to receive pension affects the fundamental right of the petitioner under Articles 19(1)(f) and 31(1) of the Constitution, and as such the writ petition under Article 32 is maintainable....."

(7.2) Thereafter, the Supreme Court in the matter of D. S. Nakara & others v. Union of India<sup>3</sup> reiterating the law laid down in Deokinandan Prasad (supra) held as under:-

"28. Pensions to civil employees of the Government and the defence personnel as administered in India appear to be a compensation for service rendered in the past. However, as held in Douge v. Board of Education [302 US 74 : 83 L Ed 57] a pension is closely akin to wages in that it consists of payment provided by an employer, is paid in consideration of past service and serves the purpose of helping the recipient meet the expenses of living....."

29. ....Thus the pension payable to a government employee is earned by rendering long and efficient service and therefore can be said to be a deferred portion of the compensation or for service rendered....."

(7.3) Similar is the proposition laid down in Sudhir Chandra Sarkar v. Tata Iron and Steel Co. Ltd. and others<sup>4</sup> in which their Lordships after taking note of Deokinandan Prasad (supra) and

<sup>3</sup> (1983) 1 SCC 305

<sup>4</sup> (1984) 3 SCC 369

D. S. Nakara (supra) held that pension is a right and payment of it doesn't depend upon the discretion of the employer nor it can be denied at the sweet will or fancy of the employer.

(7.4) A three-judge Bench of the Supreme Court in the matter of State of West Bengal v. Harish C. Banerjee and others<sup>5</sup> relying on Deokinandan Prasad (supra) and D. S. Nakara (supra) clearly held that right to receive pension is a valuable right of the government servant which doesn't depend upon the sweet will and pleasure of the government and succinctly held as under:-

"4. Pension is not a bounty payable on the sweet will and the pleasure of the Government and to receive pension is a valuable right of a government servant is a well-settled legal proposition. The question in the present case, however, is not about the deprivation of the said right by the Government by an executive order but is about the constitutional validity of Rule 10(1) providing for withholding of pension or part thereof in certain cases.

5. Articles 19(1)(f) and 31(1) have been repealed by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978 w.e.f. 20-6-1979. The right to property is no longer a fundamental right. It is now a constitutional right, as provided in Article 300-A of the Constitution. Right to receive pension was a fundamental right at the time of framing of the Rules in 1971. The question is whether a rule framed under proviso to Article 309 of the Constitution providing for withholding of the pension would ipso facto be ultra vires, being violative of Article 19(1)(f) as it stood in 1971 when the Rules were framed."

(7.5) In Pepsu Road Transport Corporation, Patiala v. Mangal Singh and others<sup>6</sup>, the Supreme Court has considered the nature and object of pension and held as under:-

<sup>5</sup> (2006) 7 SCC 651

<sup>6</sup>

"34. Pension is a retirement benefit partaking of the character of regular payment to a person in consideration of the past services rendered by him. We hasten to add that although pension is not a bounty but is claimable as a matter of right, yet the right is not absolute or unconditional. The person claiming pension must establish his entitlement to such pension in law....."

39. Pension is a periodic payment of an amount to the employee, after his retirement from service by his employer till his death. In some cases, it is also payable to the dependants of the deceased employee as a family pension. Pension is in a nature of right which an employee has earned by rendering long service to the employer. It is a deferred payment of compensation for past service. It is dependable on the condition of rendering of service by the employee for a certain fixed period of time with decent behaviour. Like CPF, the object of providing pensionary benefit under the Pension Scheme is to provide social security to the employee and his family after his retirement from the service. The Government's/employer's obligation under the Pension Scheme begins only when the employee retires and it continues till the death of the employee.

49. .... Pension is not a charity or bounty nor is it a conditional payment solely dependent on the sweet will of the employer. It is earned for rendering a long and satisfactory service. It is in the nature of deferred payment for the past services. It is a social security plan consistent with the socio-economic requirements of the Constitution when the employer is State within the meaning of Article 12 of the Constitution rendering social justice to a superannuated government servant. It is a right attached to the office and cannot be arbitrarily denied."

(7.6) In the matter of State of Jharkhand v. Jitendra Kumar Shrivastava and another<sup>7</sup>, it has been held by their Lordships of the Supreme Court that gratuity and pension are not bounty and it is thus a hard earned benefit which accrues to an employee and



is in the nature of property. This right to property cannot be taken away without the due process of law as per the provisions of Article 300-A of the Constitution of India. It has been held following the decisions of the Supreme Court in the matter of Deokinandan Prasad (supra) and D. S. Nakara (supra). The report states as under:-

"It is an accepted position that gratuity and pension are not the bounties. An employee earns these benefits by dint of his long, continuous, faithful and unblemished service. Conceptually it is so lucidly described in D. S. Nakara (supra) by Justice D. A. Desai, who spoke for the Bench, in his inimitable style, in the following words:

18. The approach of the respondents raises a vital and none too easy of answer, question as to why pension is paid. And why was it required to be liberalised? Is the employer, which expression will include even the State, bound to pay pension? Is there any obligation on the employer to provide for the erstwhile employee even after the contract of employment has come to an end and the employee has ceased to render service?

19. What is a pension? What are the goals of pension? What public interest or purpose, if any, it seeks to serve? If it does seek to serve some public purpose, is it thwarted by such artificial division of retirement pre and post a certain date? We need seek answer to these and incidental questions so as to render just justice between parties to this petition.

20. The antiquated notion of pension being a bounty, a gratuitous payment depending upon the sweet will or grace of the employer not claimable as a right and, therefore, no right to pension can be enforced through Court has been swept under the carpet by the decision of the Constitution Bench in Deokinandan Prasad v. State of Bihar (supra) wherein this Court authoritatively ruled that pension is a right and the payment of it does not depend upon the discretion of the Government but

is governed by the rules and a government servant coming within those rules is entitled to claim pension. It was further held that the grant of pension does not depend upon anyone's discretion. It is only for the purpose of quantifying the amount having regard to service and other allied matters that it may be necessary for the authority to pass an order to that effect but the right to receive pension flows to the officer not because of any such order but by virtue of the rules. This view was reaffirmed in State of Punjab v. Iqbal Singh<sup>8</sup>

It is thus hard earned benefit which accrues to an employee and is in the nature of "property". This right to property cannot be taken away without the due process of law as per the provisions of Article 300-A of the Constitution of India.

14. The right to receive pension was recognized as a right to property by the Constitution Bench judgment of this Court in Deokinandan Prasad v. State of Bihar (supra)."

(7.7) Very recently, in the matter of State of Himanchal Pradesh & others v. Rajesh Chander Sood & others<sup>9</sup>, their Lordships of the Supreme Court referred the judgment of Deokinandan Prasad (supra) and D. S. Nakara (supra) with approval.

(7.8) In a very recently delivered judgment by the Supreme Court in the matter of State of Uttar Pradesh & others Vs. Dharendra Pal Singh<sup>10</sup> following the principle of law laid down in State of Kerala and others Vs. M. Padmanabhan Nair<sup>11</sup>, it has been held that culpable delay in disbursement of payment of gratuity must be visited with penalty of payment of interest.

<sup>8</sup> (1976) 2 SCC 1

<sup>9</sup> (2016) 10 SCC 77

<sup>10</sup> (2017) 1 SCC 49

<sup>11</sup> (1985) 1 SCC 429

(8) Thus, from the above-stated binding judgments of the Supreme Court, it is luminously clear that a person cannot be deprived of pension without authority of law as it is property within the meaning of Article 300 of the Constitution of India and, therefore, deprivation of the same is clearly untenable and without authority of law.

(9) Not only this, the Supreme Court in the matter of *M. Padmanabhan Nair (supra)* has clearly held that pension and gratuity are no longer any bounty to be distributed by the Government to its employees on their retirement but have become, under the decision of this Court, valuable rights and property in their hands and any culpable delay in settlement and disbursement thereof must be visited with penalty of payment of interest at the current market rate till actual payment and granted 6% interest per annum as claimed by the petitioner therein.

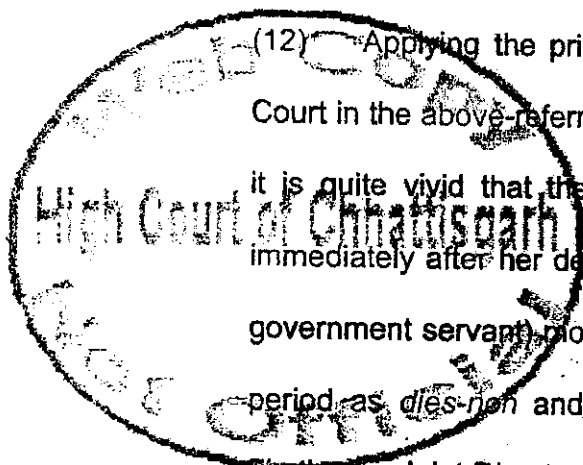
(10) The above stated judgment rendered in the matter of *State of Kerala and others (supra)* has been followed with approval by the Supreme Court in the matter of *D.D. Tewari (dead) through Legal representatives Vs. Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited and others*<sup>12</sup>, in which their Lordships of the Supreme Court have awarded 9% interest per annum and further directed that if the amount is not paid within the stipulated period, then the same shall carry interest at the rate of 18% per annum from the

<sup>12</sup> (2014) 8 SCC 894

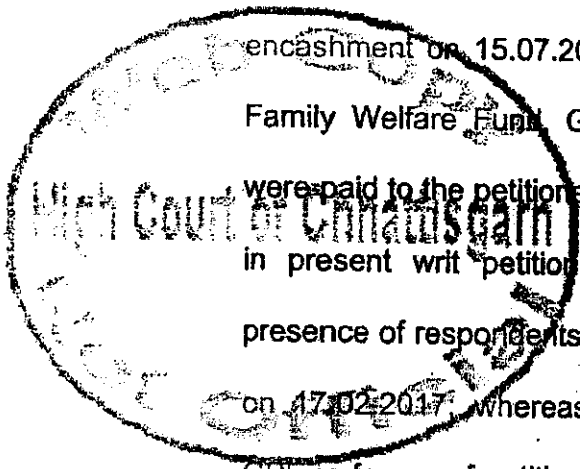
date when the amount falls due to the deceased.

(11) As noticed in opening paragraph of this order, the Supreme Court in the matter of **Vijay L. Mehrotra** (supra) clearly held that all the payments of retiral dues should be paid on the date of retirement or immediately thereafter and finding no justification for delay in making payments awarded simple interest at the rate of 18% per annum with effect from date of her retirement till date of actual payment.

(12) Applying the principle of law laid down by the Supreme Court in the above-referred cases to the facts of the present case, it is quite vivid that the petitioner's wife died on 7.2.1999 and immediately after her death, petitioner (husband of the deceased government servant) moved an application declaring the absence period as *dies non* and for grant of admissible retiral benefits. Firstly, the Joint Director, Pension did not take any prompt step for declaring the absence period as *dies non* and made objection one after the other, and the said application was ultimately forwarded to the Director, Health Services, Raipur on 9.5.2001 for declaring the said period as *dies non* but the Director, Health Services sitting tight over the matter did not take decision on the said application promptly till the order was passed in the writ petition filed by the petitioner on 26.04.2011 by this Court, then only on 27.07.2011 the Director, Health Services declared the period of absence of deceased government servant as *dies non* and,



thereafter, the Joint Director, Pension granted the amount of pension and death-cum-retirement gratuity on 28.10.2011. Once the period of absence is declared dies non, the Chief Medical & Health Officer, Ambikapur and Block Medical Officer, Kusmi, District Balrampur should have taken prompt steps to pay all retiral benefits admissible such as leave encashment, family welfare fund, General Insurance Scheme and Group insurance, but the Chief Medical & Health Officer, Ambikapur/Block Medical Officer, Kusmi remained happy by granting an amount of leave encashment on 15.07.2014. The other admissible dues such as Family Welfare Fund, General Insurance and Group Insurance were paid to the petitioner as late as on 3.2.2017 when this Court in present writ petition on 30.01.2017 directed the personal presence of respondents No. 3 & 6 and fixed the case for hearing on 17.02.2017 whereas proposal for releasing the amount of GPF in favour of petitioner was made to the Accountant General only after on 7.1.2017 when this Court directed for filing of the return in this writ petition. It appears from the return filed in this petition that the office of Accountant General has made request to the Block Medical Officer, Kusmi, District Balrampur for sending the case of petitioner for grant of amount of General Provident Fund, then only the proposal was made on 7.1.2017 by Block Medical Officer to the Accountant General for grant of pension to the petitioner.



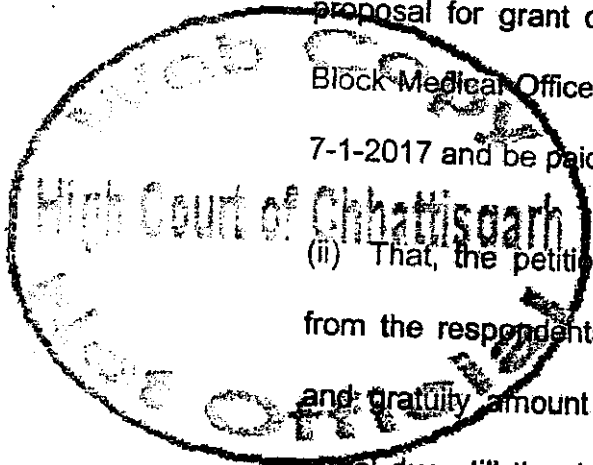
(13) The aforesaid sequence of events would show that there is complete callousness and indifferent attitude firstly on the part of Director, Health Services, Raipur, who took more than 11 years in declaring the absence period of deceased government servant as *dies non*, that too, pursuant to the order of this Court in writ petition filed by petitioner. Secondly, the Chief Medical & Health Officer, Ambikaur and Block Medical Officer, Kusumi, District Balrampur did not take prompt steps even after declaring the absence period as *dies non* on 27.07.2011 by Director (Health Services) and only an amount of leave encashment was paid by Block Medical Officer, Kusumi as late as on 15.7.2014. The amount of Family Welfare Fund, General Insurance Scheme & Group Insurance was paid only when personal presence of respondents No. 3 & 6 was directed by this Court on 17.02.2017 and the Block Medical Officer has already stated that proposal for GPF was made only on 7.1.2017 pursuant to the order of Accountant General and there is complete violation of Rules of 1976 in making payment of retiral dues to the petitioner particularly breach of Rule 69(8) of the Rules of 1976.

(14) In the considered opinion of this Court, it is a complete callousness and the culpable delay on the part of Director, Health Services, Raipur, Chief Medical & Health Officer, Ambikapur and Block Medical Officer, Kusmi, District Balrampur, Ramanujanj, in making payment of retiral dues to the petitioner and further taking

into account that such a lapse on the part of the Authorities of the State Government is a regular phenomenon, giving feeling of insecurity in the mind of the government servant in getting their retiral dues right in time and to avoid the culpable delay in making the payment of retiral dues, this writ petition is disposed of with the following directions:-

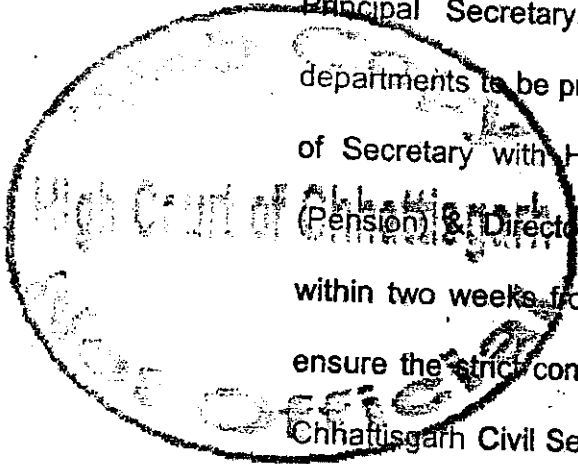
(i) That, the Accountant General shall take a decision on the petitioner's case for grant of GPF within six weeks as the proposal for grant of GPF has already been sent by the Block Medical Officer, Kusumi, District Balrampur to him on 7-1-2017 and be paid at the earliest.

(ii) That, the petitioner will be entitled for interest @ 8% from the respondents on the delayed payment of pension and gratuity amount from the date of entitlement of such retiral dues till the date of actual payment. The amount be paid within a period of six weeks, failing which, it will carry interest @ 10% per annum. The petitioner will also be entitled for cost of Rs.25,000/- from the Director, Health Services as petitioner was required to file two writ petitions for disbursement of retiral dues and incurred huge expenses in prosecuting these writ petitions and suffered harassment & trauma. The State Government is at liberty to consider whether erring official should or should not be directed to compensate the government or loss sustained by it by his



culpable lapses, such action if taken would help generate in the officials of the State Government a sense of duty towards the Government under whom they serve as also a sense of accountability to members of the public as mandated by Supreme Court in the matter of **State of Kerala Vs. M. Padmnabhan Nair (supra)**.

(iii) The Chief Secretary, Govt of Chhattisgarh is directed to constitute a committee with consultation of Principal Secretary, GAD in each of its government departments to be presided by an officer not below the rank of Secretary with Head of the Department and Director (Pension) & Director (Local Audit Fund) as its members within two weeks from the date of receipt of this order to ensure the strict compliance of provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services Pension Rules, 1976 relating to disbursement of retiral benefits and to ensure that process for timely payment of retiral dues is initiated well in advance and retiral benefits be paid to retiring government employee on the date of retirement itself as per rules and/or to the legal representatives of the deceased government servant as per Rule 69 (8) of the Rules of 1968, keeping in view the mandate of the Supreme Court in the matter of **Vijay L. Mehrotra (Supra)**, in which it has been expected by their Lordships that retiral dues should be paid to the





Government servant on the date of his retirement, except in case in which for unforeseen circumstances it cannot be paid. The said Committee shall ensure the strict compliance of the Rules of 1976 by holding meetings monthly and, thereafter, every month's report be sent to Chief Secretary the result of meeting & difficulty, if any, in disbursement of retiral dues to retiring Government Servant and in turn, Chief Secretary will consider their reports and give necessary direction in that behalf and monitor cases by holding meeting of the said committee quarterly and to ensure that files of retiring government servants relating to retiral benefits, should not be kept pending at any level undecided and be paid well in time. The Chief Secretary, Government of Chhattisgarh will submit action taken report after three months to this Court.

(iv) A copy of this order be sent to the Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh and also to Principal Secretary, GAD for information and needful. The Principal Secretary, GAD is directed to convey a copy of this order to all District Collectors, who in turn, in Time Limit meeting bring into the notice of all responsible officers entrusted with the duty of dealing with/clearing the file of retiral dues of retiring government servant and to ensure due compliance of this order and Rules of 1976. The Principal Secretary, GAD is

further directed to send a copy to the Commissioner (Revenue) of all the Revenue Divisions and Commissioner in turn, quarterly review the cases relating to retiring government servant in presence of the Collector (s) of the concerned Revenue Division to ensure the compliance of the Rules of 1996 and payment of retiral dues to retiring government servant right in time.

(v) A copy of this order be sent directly to Director (Pension) & Director (Local Audit Fund), who in turn circulate it among all its Joint Director (Pension) & (Local Audit Fund) of all the Districts to ensure that the files relating to retiral dues be cleared by their respective Joint Director (s) right in time as per rules and should not be unreasonably delayed at their level and must act consistent with the Rules of 1976.

(15) The writ petition is disposed of accordingly.

Sd/-

(Sanjay K. Agrawal)  
Judge

D/-

**HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR**

**W.P. (S) No. 5256 of 2016**

**Shyam Dev**

**Versus**

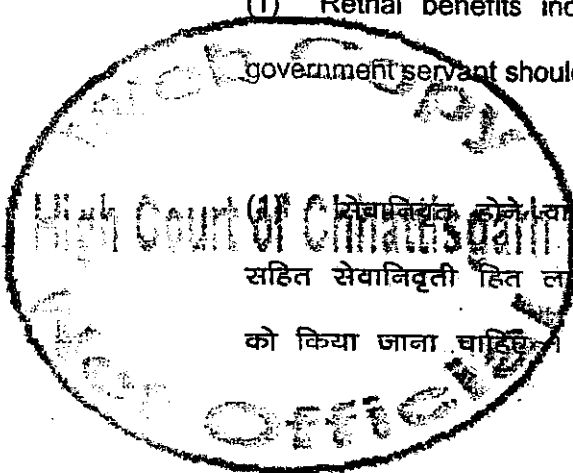
**State of Chhattisgarh & others.**

**English**

(1) Retrial benefits including pension and gratuity of a retiring government servant should be paid on the date of his retirement.

**Hindi**

(1) सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय कर्मचारी की पेंशन एवं उपदान सहित सेवानिवृत्ति हित लाभों का भुगतान उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि को किया जाना चाहिये।



छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 26/04/2017

कमांक एफ 20-1/2017/1/3 - राज्य शासन एतद्वारा रिट पिटिशन (एस)क. 5256/2016-श्याम देव विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में मान. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.2.2017 की कंडिका 14(iii) में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, शासन के सभी विभागों में सेवानिवृत्त होने वाले/सेवाकाल के दौरान मृत शासकीय सेवकों के देय स्वत्वों का भुगतान संबंधित को समय पर सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार समिति गठित करता है :-

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. विभाग का भारसाधक सचिव          | - अध्यक्ष |
| 2. विभागाध्यक्ष                   | - सदस्य   |
| 3. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन    | - सदस्य   |
| 4. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा | - सदस्य   |

2/ उक्त समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति उपरांत मिलने वाले समस्त स्वत्वों का भुगतान/निपटारा समय पर हो तथा सेवा में रहते हुए यदि किसी शासकीय सेवक का निधन हो जाए तो समिति उसके परिवार को मिलने वाले स्वत्वों का त्वरित भुगतान/निराकरण की समीक्षा भी करेगी। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के पश्चात् देय सभी स्वत्वों का भुगतान समय पर किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में निर्धारित प्रावधानों का पालन कठोरता पूर्वक किया जाए।

3/ समिति की बैठक प्रति माह आयोजित की जाए एवं बैठक की कार्यवाही एवं निराकरण में आने वाली कठिनाईयों से प्रतिमाह मुख्य सचिव को अवगत कराया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
आदेशानुसार,

(विकास शील) 26/4/17

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

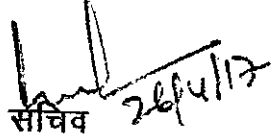
पृष्ठां क्रमांक एफ 20-1/2017/1/3

नया रायपुर, दिनांक 26/04/2017

**प्रतिलिपि :-**

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. समस्त मान. मंत्रीगण/संसदीय सचिव के विशेष सहायक/निज सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पार्क, रायपुर
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
7. महानिदेशक: प्रशासन अकादमी, निमोरा, नया रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर।
13. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
14. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालय, नया रायपुर, की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट [www.cg.nic.in/gad](http://www.cg.nic.in/gad) पर अपलोड हेतु।

**की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।**

  
सचिव 26/4/17

छत्तीसगढ़ शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग